भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2037

(11 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

असम में मनरेगा

2037. श्री जयन्त बसुमतारी:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) के अंतर्गत असम राज्य के लिए आवंटित और स्वीकृत निधि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार की एमजीएनआरईजीएस के अंतर्गत असम राज्य का निधि आवंटन बढ़ाने की कोई योजना है;

(ग) क्या सरकार को असम राज्य से एमजीएनआरईजीएस निधि बढ़ाने की कोई मांग प्राप्त हुई है;

(घ) सरकार द्वारा असम को सभी लंबित मजदूरी और सामग्री बकाया का भुगतान कब तक करने की संभावना है; और

(ङ) एमजीएनआरईजीएस को उचित रूप से कार्यान्वित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(श्री कमलेश पासवान)

(क) से (घ): महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना) एक मांग आधारित मजदूरी रोजगार योजना है। महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के अनुसार निधि का आवंटन नहीं किया जाता है। वर्ष 2021-22 से 2023-24 तक पिछले तीन वित्तीय वर्षों में महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत असम राज्य को जारी की गई निधियों का विवरण नीचे दिया गया है:

वित्तीय वर्ष	2021-22	2022-23	2023-24
असम राज्य के लिए जारी केंद्रीय निधि (करोड़ रुपये में)	2,220.26	2,052.34	2,221.38

महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत , मजदूरी का भुगतान केंद्र सरकार द्वारा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रोटोकॉल के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के खाते में जमा किया जाता है।

सामग्री घटकों के संबंध में , राज्य/संघ राज्य क्षेत्र भारत सरकार को निधि जारी करने के प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। केंद्र सरकार समय-समय पर दो खेपों में निधि जारी करती है , जिसमें प्रत्येक खेप में एक या अधिक किस्तें शामिल होती हैं , जो "सहमत" श्रम बजट, कार्यों की मांग, प्रारंभिक शेष राशि, निधियों के उपयोग की गति, लंबित देनदारियों, समग्र निष्पादन को ध्यान में रखते हुए और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रासंगिक दस्तावेज़ प्रस्तुत करने के अध्यधीन होती हैं।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए निधि जारी करना एक सतत प्रक्रिया है और केंद्र सरकार जमीनी स्तर पर कार्य की मांग के अनुसार योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

वर्तमान वित्त वर्ष 2024-25 (27.02.2025 की स्थिति के अनुसार) में असम राज्य को 1925.67 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है , जिसमें महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत सामग्री और प्रशासनिक घटकों के लिए 366.82 करोड़ रुपये शामिल हैं।

(ड.): यह मंत्रालय नियमित रूप से विभिन्न मंचों जैसे मध्यावधि समीक्षा , श्रम बजट बैठकें, श्रम बजट संशोधन बैठकें , सामान्य समीक्षा मिशन , कार्यक्रम समीक्षा समिति बैठकें , मासिक समीक्षा बैठक और केंद्रीय रोजगार गारंटी परिषद की बैठकों के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में महात्मा गांधी नरेगा योजना के कार्यान्वयन के निष्पादन की समीक्षा करता है। इसके अलावा , राज्य रोजगार गारंटी परिषदें (सीईजीसी) भी समय-समय पर राज्य स्तर पर योजना के कार्यान्वयन की निगरानी करती हैं।

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अधिनियम के प्रावधानों के साथ-साथ समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार योजना के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

1. ग्राम पंचायत स्तर पर सामाजिक लेखापरीक्षा करना
2. लोकपाल की नियुक्ति के माध्यम से शिकायत निवारण तंत्र।
3. राष्ट्रीय स्तर के निगरानीकर्ताओं और केंद्रीय दलों द्वारा निगरानी।
4. आंतरिक लेखा परीक्षा करना।
5. क्षेत्र अधिकारी ऐप के उपयोग के माध्यम से निगरानी।
6. उपस्थिति दर्ज करने के लिए राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी प्रणाली (एनएमएमएस) का उपयोग।
7. नागरिकों की प्रतिक्रिया और जानकारी प्राप्त करने के लिए जनमनरेगा ऐप।

योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए किए गए कुछ तकनीकी कार्यकलाप नीचे दिए गए हैं :

1. युक्तधारा: ग्राम पंचायत स्तर पर जीआईएस आधारित योजना को सरल बनाने के लिए , इसरो-एनआरएससी के सहयोग से भू-स्थानिक आयोजना पोर्टल युक्तधारा विकसित किया गया है।

2. सिक्योर - रोजगार के लिए ग्रामीण दरों का उपयोग करने के लिए अनुमान गणना हेतु सॉफ्टवेयर: इस एप्लिकेशन का उपयोग योजना के तहत किए जाने वाले कार्यों के अनुमान की गणना के लिए किया जा रहा है।

3. जियो-मनरेगा: इस ऐप को परिसंपत्तियों के निर्माण को जियोटैग करके ट्रैक करने के लिए विकसित किया गया है , ताकि परिसंपत्ति निर्माण के "पहले", "दौरान" और "बाद" के चरणों में परिसंपत्तियों के निर्माण को ट्रैक किया जा सके। अब तक , कुल 6.26 करोड़ परिसंपत्तियों को जियोटैग किया जा चुका है।

4. प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी): प्रणाली में अधिक पारदर्शिता लाने और लीकेज को कम करने के लिए, मजदूरी भुगतान में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) प्रणाली को अपनाया गया है। कार्यक्रम के तहत, मजदूरी के 99% से अधिक भुगतान इलेक्ट्रॉनिक रूप से डीबीटी प्रणाली के माध्यम से श्रमिकों के खातों में जमा किए जाते हैं।

5. आधार भुगतान ब्रिज सिस्टम: डीबीटी प्रोटोकॉल का पालन करते हुए लाभार्थियों के खातों में मजदूरी का भुगतान आधार भुगतान ब्रिज प्रणाली के माध्यम से किया जाता है। कुल 13.52 करोड़ सक्रिय श्रमिकों में से 13.45 करोड़ सक्रिय श्रमिकों को आधार से जोड़ा जा चुका है।